Thirteenth Loksabha

Session: 13 Date: 06-08-2003

Participants: Yadav Shri Mulayam Singh ,Paswan Shri Ram Vilas ,Dasmunsi Shri Priya Ranjan ,Pal Shri Rupchand ,Chakraborty Shri Ajay ,Chatterjee Shri Somnath ,Khan Shri Sunil ,Bandyopadhyay Shri Sudip ,Sushma Swaraj Smt.

Title: Regarding situation arising out of increasing unemployment in the country.

12.57 hrs.

(ii) RE: UNEMPLOYMENT SITUATION IN THE COUNTRY

MR. SPEAKER: The question of employment was raised by Shri Mulayam Singh Yadav and I had also permitted him on the issue. Now, I want to listen to Shri Ram Vilas Paswan . मुलायम सिंह जी, आपको इस वाय पर और कुछ कहना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अभी तो हम बोले ही नहीं हैं।...(व्यवधान)

श्री वी.धनञ्जय कुमार (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, 165 किसानों ने आत्महत्या की है। यह विाय इससे भी ज्यादा गंभीर है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विाय के बाद मैं आपको इजाजत देना चाहता हूं।

श्री वी.धनञ्जय कुमार : इतने सारे लोग उस साइड से बोले हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विाय पर झगड़ा करने की जरुरत नहीं है कि मैं किसको इजाजत पहले दुं।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: There is no Adjournment on this. मैं इस विाय पर डिसकशन एलाउ नहीं कर रहा हूं। यह क्या एडजर्नमेंट मोशन का विाय है? अनएम्पलॉयमेंट का विाय है। यह बहुत गंभीर विाय है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए सदन में चर्चा करिए। यह एडजर्नमेंट मोशन का विाय नहीं हो सकता।

...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदय : इस पर ज़ीरो ऑवर में डिबेट कैसे होगी ?

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने विाय को गंभीरता से लिया है और यह बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। इस बेरोजगारी के कारण...(<u>व्यवधान</u>)

MR. SPEAKER: You must have sympathy for that Member also.

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय बेरोजगारी के कारण देश की बहुत भयावह स्थिति हो गई है। सबसे बड़ी ि वडम्बना यह है कि प्रधान मंत्री जी ने सत्ता संभालते ही घोाणा की थी कि एक करोड़ नौजवानों को रोजगार प्रतिर्वा देंगे और उसी के संबंध में इनके वचन को पूरा करने की संभावनाओं पर विचार के लिये योजना आयोग ने अपने

सदस्य मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था । अहलूवालिया कमेटी की रिपोर्ट 2001 में आई जिसमें 10 करोड लोगों को दस साल में रोजगार देने की बात कही गई। 1993-1994 में बेकारी की दर 6.03 प्रतिशत थी और 2000 यह दर बढ़कर 7.32 प्रतिशत हो गई। साथ ही गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालो की तादाद 26% हो गई । उन्होंने कहा की यदि विकास की दर 6.5 प्रतिशत टिकी रही तो 50 लाख से अधिक लोगों को हर साल रोजगार देना सम्भव नही है जो प्रधान मंत्री जी ने उम्मीद की थी, उस पर रोजगार के अवसर कैसे ढूंढ़े जाएं, कैसे खोजे जाएं, इस संबंध में रिपोर्ट में स्पट बताया गया कि यदि प्रधानमंत्री को वायदा पूरा करना है तो तरक्की की रफ्तार 9 से 10 प्रतिशत पर लानी होगी । इसके लिये भारी निवेश की आवश्यकता है जो भारत में संभव नहीं है(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, अभी ये सब बातें आप जब चर्चा हो तब बोल सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : चर्चा में बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी इस विाय पर चर्चा नहीं है। अभी इस पर डिबेट शुरू नहीं हुई है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : इसीलिए चर्चा इस पर होनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा के लिए सहमति देने के लिए तैयार हूं। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के आप भी मैम्बर हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं कहना चाहता हूं कि कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ही यह कहा गया कि 6 फीसदी विकास दर टिकी रही तो प्रधान मंत्री जी का दस करोड़ रोजगार का देना दिवा स्वप्न होगा।

13.00 hrs.

समिति की रिपोर्ट में स्पट बताया गया कि जब तक देश की विकास दर नौ से दस फीसदी नहीं होगी, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने जो वादा किया है, वह दिवास्वप्न हो जाएगा। इस रिपोर्ट पर संघ परिवार व राजग में विवाद पैदा हो गया क्योंकि एक करोड रोजगार के वादे को हवाई कर दिया। इसलिये 2002 में डा. एस.पी. गुप्ता कमेटी बनाई गई । उनके अनुसार 1993-94 में बेकारी की रफ्तार 7.3 % थी और 2000 में 6 % हो गई। उन्होंने भी माना 2000 में 2.70 करोड लोग बेकार हो गये । दोनो कमेटियों ने माना कि मौजूदा विकास दर पर एक करोड लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता । हमारी आपसे प्रार्थना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देश की स्थिति बहुत गम्भीर है, भयावह स्थिति है। दस करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। केरल, आंध्र प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में ज्यादा बेरोजगारी दिखाई देती है, क्योंकि वहां पढ़े-लिखे बेरोजगार ज्यादा हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में अशिक्षित ज्यादा हैं इसलिए उनकी समस्या का पता नहीं चल पाता, जबिक वहां ज्यादा बेरोजगारी है। केवल बेकारी को छिपाने के लिये सर्वशिक्षा से साजिश करके वंचित किया जा रहा है । इन्हीं दोनो राज्यों से आबादी का सर्वाधिक पलायन है।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी इस पर चर्चा नहीं कर सकते, सिर्फ एक-दो मुद्दों पर अपनी बात कह सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरा निवेदन है कि इन दोनों कमेटीज की रिपोर्ट के आधार पर सदन के अंदर कम से कम दो से तीन दिन तक बहस कराई जाए, क्योंकि देश में रोजगार की स्थिति बड़ी खराब और भयावह है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विाय पर चर्चा की अनुमित दी और इस पर बोलने का मौका दिया। जिस दिन से संसद का यह सत्र शुरू हुआ है, तब से प्रतिदिन मैं नोटिस दे रहा हूं। कभी स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से और कभी प्रश्न काल स्थगित करने के माध्यम से मैं नोटिस दे रहा हूं। हमारी पार्टी के करीब 25,000 युवकों ने बारिश के मौसम में इस सम्बन्ध में गिरफ्तारी भी दी है। हम देख रहे हैं कि इस देश के प्रजातंत्र पर एक दिन खतरा होगा, उसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी की समस्या होगा। हम

लोगों को इस बात की पीड़ा नहीं हो रही है, क्योंकि हमें रोजगार प्राप्त है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या सबसे भया वह समस्या है। गांवों से लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं। शहरों में भी सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता।

श्री राम विलास पासवान: इसकी क्या तुक है, फिर एक बजे आप सदन को एडजोर्न कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि यह विाय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस पर चर्चा की अनुमति बाद में दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : अभी कोकाकोला के विाय पर सरकार जवाब दे सकती थी, उस पर एक घंटे तक चर्चा हुई। बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसीलिए इस विाय पर सदन में चर्चा कराने की अनुमति दे रहा हूं, तब आप बोल सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : उसके पहले आप हमारी बात तो सुन लें कि हम क्या कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता।

श्री राम विलास पासवान : नहीं देना चाहते, तो हम बैठ जाएंगे। हम लोग किसी ऊल-जलूल विाय पर नहीं बोलते हैं। बैठे रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत दी है इसलिए आप एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, कल आपने सदन में एक प्रश्न का सरकार का जवाब सुना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप इस विाय पर चर्चा कराएंगे तो सरकार की तरफ से कौन जवाब देगा। आपने कल देखा होगा कि बेरोजगारी के सवाल पर जब एक प्रश्न आया तो सरकार जवाब देने में बिल्कुल अक्षम साबित हुई। आप सदन के मालिक हैं, सदन का पांच साल का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। जैसा मुलायम सिंह जी ने कहा कि सरकार ने घोाणा की थी कि हम हर साल एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन पांच साल में पांच करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। दस साल में सिर्फ 43 लाख लोगों को वह भी रूरल इम्प्लायमेंट के तहत रोजगार दिया गया है। सरकार की तरफ से हजारों योजनाएं चल रही हैं। प्रधान मंत्री रोजगार योजना, सम्पूर्ण रोजगार योजना आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक रोजगार की गारंटी, इम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम चालू नहीं होगी, जब तक संविधान में रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकारों में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। 1990 में जब मैं लेबर मिनिस्टर था तो मैंने राज्य सरकारों से बातचीत की थी और तीन बार बातचीत की थी। राज्य सरकारों को भी थोड़ी जवाबदेही लेनी होगी। केन्द्र सरकार को मेजर शेयर देना पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ा जाए, इसके ऊपर डिसकशन होना चाहिए। बेरोजगारी का सवाल उसीमें अपने आप जुड़ जाएगा। हमारी मांग है कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा जाए। इसके अलावा जो योजनाएं चल रही हैं, जिनमें इतनी लूट हो रही है, उन सबको जोड़कर एक इम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के तहत लाया जाए।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Speaker Sir, first of all, I request you to advise the Government to be prepared for a full two-day debate on this matter in the presence of the full Cabinet because the issues are inter-linked with various Ministries, including the Planning Commission.

The Annual Report prepared by this very Government for the year 2001-02, by the Ministry of Labour gives an alarming picture at Page 226 where the Government concedes that the planning process may need time to define an independent employment strategy. The Report further says that the rate of growth of employment which was 2.37 per cent per year during 1987 to 1994, declined to 1.05 per cent per year during 1993 to 2000.

The latest figure is that it is less than one per cent up to 2003. In this alarming situation, I apprehend that there will be a serious unrest in the country, both in the villages and in the urban areas. The Parliament, especially the Opposition is being accused by various sections of the House, including the Party in power, that the Opposition never brings issues which are important to the people. Here is an issue which is very important to the people. Nothing could be more important than this. The hon. Prime Minister is committed towards this. The entire Ministry is committed.

Therefore, I demand that a full two-day debate should be allowed. The full Cabinet should be present along with the Prime Minister. The Government should give a comprehensive reply as to why in the Tenth Plan a definite employment target has not been fixed. It is only growth oriented. The hon. Prime Minister had announced that there will be a growth rate of eight per cent. We may or may not achieve that target. But on employment generation, the Government is silent. We demand a full two-day discussion. The hon. Prime Minister must reply to this debate.

MR. SPEAKER: I am giving only one or two minutes to speak. We can discuss it in detail during the debate.

SHRI RUP CHAND PAL (HOOGLY): In the midst of a very alarming and grave unemployment situation in the country, everyday we find in the newspapers that in some parts of the country, some units of either the private sector or the public sector are being closed down. Even yesterday there was a news item that Indian Telephone Industry has decided to retrench some employees. It is one of the most prestigious industries in the country. I had occasions to examine them. They had deposed that the potential for growth of this industry is very high. When the telecom sector has been opened up and when a claim is being made that this is one sector which has a lot of growth potential, 11,000 employees have been thrown out of employment. In spite of an assurance from the Government regarding making available employment, there is no employment either in agriculture sector or in semi-urban areas or in urban areas. Nor is there employment for the educated people.

MR. SPEAKER: We can discuss it in detail during the debate.

SHRI RUP CHAND PAL: Mr. Speaker, Sir, we need a full-fledged discussion when the Government can come out with a plan so that the people of this country can know what is the plan of this Government as far as creating new employment opportunities is concerned.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Mr. Speaker, Sir, thank you. The problem of unemployment is a burning problem in our country. This is a paramount issue and a paramount question in our country. Lakhs of youths who are registered in the employment exchanges are not getting employment. Unemployed people are very frustrated. A large number of industries are being closed down everyday. Thousands and thousands of employees and workers are being thrown out of their jobs. This Government assured the nation that it would provide one crore jobs every year.

MR. SPEAKER: Everybody is mentioning this.

SHRI AJOY CHAKRABORTY: But their jobs are being snatched away. This is a paramount problem and a burning problem.

MR. SPEAKER: Please sit down. Your time is over. You can only support this. I am going to allow a debate on this, if approved by the Business Advisory Committee.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय: धनंजय कुमार जी का विाय जहां 150 लोग मारे गये हैं, वह विाय मुझे चाहिए। इसलिए मैं उनको पर्मीशन दे रहा हूं।

SHRI AJOY CHAKRABORTY: My only demand is that right to employment should be incorporated as a fundamental right in the Indian Constitution.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Mr. Speaker, Sir, nobody will dispute that this is an important issue. I am sure the Government will also concede this debate. It is because here the accountability is to the people. Of course, the accountability to the Parliament is also there. Therefore, nobody can minimise the seriousness of this issue. Therefore, we request that you kindly fix an early date to discuss this matter. It is a very serious matter.

SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): I am supporting him.

MR. SPEAKER: Shri Bandyopadhyay, you can only make a statement like him.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Mr. Speaker, Sir, the problem of unemployment is skyrocketing. In a State like West Bengal, a Party is in power for the last twenty-six years.

The highest number of unemployed youth is registered in West Bengal. Why can they not give any guidelines to the State concerned.... (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not the issue before the House. Shri Dhananjaya Kumar to speak now. Please sit down.

... (Interruptions)

श्री अकबर अली खांदोकर (सेरमपुर) : महोदय, ये क्या बोल रहे हैं, क्या आपका प्रोटैक्शन नहीं मिलेगा?

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरा प्रोटैक्शन मिलेगा।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I do not want a quarrel on this. There is no room for any quarrel on this. Everywhere, it is the same problem which exists.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please go to your seat. What is this? I have permitted Shri Dhananjaya Kumar to speak.

... (Interruptions)

श्रीमती सुामा स्वराज: महोदय, मैं सरकार की ओर से केवल इतना कहना चाहती हूं, माननीय सदस्य ने इस विाय पर जो चर्चा की मांग की है, अगली बीएसी की मीटिंग में इस के लिए समय तय कर लेंगे। (व्यवधान) MR. SPEAKER: Hon. Members, you do not want the other Members to raise their issues. Please sit down. Every Member must sit down now when I am on my legs.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not good. This is not the issue before the House. Shri Dhananjaya Kumar, you can bring your issue on record. Please go ahead with it. I have permitted you to speak and you can speak now.

... (Interruptions)